(ग) सरकार द्वारा विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी बढ़ाने हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) जी, नहीं। विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी जो वर्ष 1991 में 0.534 प्रतिशत रही थी वह वर्ष 1992 (वह वर्ष जिसके लिये विश्व व्यापार के आंकड़े सुलभता से उपलब्ध हैं) में बढ़कर 0.568 प्रतिशत हो गयी।

(ग) सरकार की नीति यह है कि विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में दीर्घावधि आधार पर विश्वव्यापीकरण को सुकर बनाया जाए और निर्यात में वृद्धि की जाये। इस बात के भी प्रयास किये जा रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका और इजरायल जैसे नये देशों को निर्यात बढ़ाया जाये। निर्यात संवर्धन एक सतत प्रक्रिया है और नई जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से समय-समय पर इसमें नीतिगत/क्रियाविधि संबंधी परिवर्तन किये जाते हैं।

चीनी - निर्यात हेतु निर्धारित लक्ष्य

828. श्री सत्य प्रकाश मालवीय :
श्री अनंतराम जायसवाल :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के वित्तीय वर्षों के दौरान चीनी निर्यात हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे और वर्ष-वार कितना चीनी निर्यात किया गया था और उनकी दरें क्या थीं ;

(ख) क्या वित्तीय वर्ष 1994-95 हेतु चीनी का कोई निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया गया है और यदि हां, तो कितना और किस दर पर ;

(ग) मुक्त सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1994-95 में 15 जुलाई तक चीनी का कितना आयात किस दर पर किया गया है

(घ) क्या यह सच है कि देश की कई बन्दरगाहों पर भारी मात्रा में आयातित चीनी बिना दावेदारी के पड़ी है जिसे वहां से उठाने को कोई सरकारी क्षेत्र का उद्यम उपक्रम तैयार नहीं है; और

(ङ) यदि हां, विभिन्न बन्दरगाहों पर आयातित चीनी की कितनी मात्रा पड़ी हुई है और इसे सरकारी गोदामों में न लाये जाने के क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) चीनी वर्ष (30 सितं० को समाप्त) के आधार पर वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान निर्यात की गई चीनी की मात्रा निम्नानुसार रही:-

वर्ष	लाख मी० टन
1992-92	5.83 नेपाल सहित
1992-93	3.97 नेपाल सहित
1993-94 (जन० 94) तक	0.31 नेपाल सहित

*अनन्तिम ।

इन वर्षों के दौरान निर्यात की गई चीनी की मात्रा के वर्षवार मूल्य संबंधी जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) जहां तक चीनी वर्ष 1994-95 का संबंध है, निर्यात हेतु संभावित उत्पादन और बेशामाल, यदि कोई हुआ, तो उसकी स्पष्ट तस्वीर मिलने के बाद ही कोई विचार बनाया जायेगा।

(ग) खाद्य मंत्रालय ने, जो कि मुक्त सामान्य लाइसेंस के तहत प्राइवेट पार्टियों द्वारा किये जा रहे चीनी आयात की मानीटरिंग कर रहा है, बताया है कि दिनांक 27-7-1994 की स्थिति के अनसार, ऐसे चीनी आयात की कुल 8.92 लाख मी0 टन मात्रा में से 6.24 लाख मी0 टन चीनी भारतीय बन्दरगाहों पर पहुंच गई है। प्राइवेट पार्टियों द्वारा किये गये इस आयात की आयात-कीमत संबंधी पूर्ण जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।

(घ) ऐसी कोई जानकारी ध्यान में नहीं आई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

Lowering of India's Listing as violator of IPR

829. DR. BAPU KALDATE:

SHRIMATI KAMLA SINHA:

MISS SAROJ KHAPARDE:

SAMBHAJIRAO SHINDE:

SHRIMATI VEENA VERMA:

SHRI RAJNI RANJAN SAHU:

SHRI RAJUBHAI A. PARMAR:

MISS SAROJ KHARARDE:

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that US administration has lowered India's listing as a violator of Insellectusal Property Rights from the priority countries;

(b) if so, what are the reason's therefor; and

(c) what is Government reaction's thereto?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI PRANAB MUKERJEE): (a) Yes, Sir.

(b) The announcement by the US-TR states that India has begun to progress towards providing modern intellectual property protection by enacting a new copyright law and by introducing improved trade mark legislation.

(c) The Government has noted the U.S. decision and expressed the hope that the multilateral rules embodied in the Uruguay Round Agreement would be respected by all signatories.

Anti-dumping petition by SAIL

830. SHRIMATI SARLA MAHESWARI:

SHRI V NARAYANASAMY:

SHRI G. Y. KRISHAN:

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that 'SAIL' has filed an anti-dumping petition with Government with reference to import of steel plates;

(b) if so, what are the findings in this regard and how government have responded to their applications; and

(c) what special measures have been taken by Government to check such dumping?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): (a) and (b) Yes, Sir. The Steel Authority of India (SAIL) had filed a request for initiating anti-dumping investigation, in February 1994 alleging dumping of steel plates into India.

The petition was examined in accordance with the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on dumped articles and for determination of Injury) Rules 1985 and it was found that there was no prima-